EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

TRAI's consultation paper on the National Broadcasting Policy (NBP) aims to gather input from stakeholders to formulate comprehensive guidelines for the broadcasting sector in India. The Policy is expected to address various issues, including content regulation, licensing, tariff structures, and the inclusion of new technologies and platforms like OTT services.

The draft Broadcasting Services Regulation Bill had drawn a lot of criticism, particularly regarding the inclusion of OTT platforms, highlights the evolving landscape of broadcasting and the challenges in regulating content across different mediums.

In TRAI's lingo definition of broadcasting services encompasses a broad range of communication mediums, emphasizing the transmission of audio, video, or both to a wide audience through various distribution channels, including electromagnetic waves and cables. The NBP underscores the need for comprehensive policies to govern this rapidly evolving industry.

This issue features an overview of the regulatory policies issued by the Govt.

The Indian media and entertainment (M&E) industry demonstrated remarkable resilience and growth in 2023, despite challenges posed by the pandemic. According to the annual EY report the industry expanded by 8% to reach a value of $27.9 billion. This growth, which exceeded pre-pandemic levels by 21%, underscores the industry's robustness and adaptability.

The report also highlights the rapid expansion of screens in India, with nearly a billion active screens expected by 2030. The unique characteristics of the Indian M&E market, characterized by a blend of tradition and innovation, are underscored in the report. Here, digital channels, OTT platforms, AI-powered newsreaders, traditional print media, flagship films, and short-form content coexist and thrive together, reflecting the industry's vibrant diversity and dynamic growth trajectory. The government's focus on enhancing digital infrastructure further augments the sector's potential for transformation and expansion.

Despite the growing dominance of digital channels, traditional media in India continues to exhibit growth, comprising 52% of total advertising revenues in 2023. Overall, the M&E sector in India stands at an inflection point, poised for significant transformation and growth driven by technological advancements, changing consumer preferences.

(Manoj Kumar Madhavan)

राष्ट्रीय प्रसारण नीति (एनबीपी) पर ट्राई के परामर्श पत्र का उद्देश्य भारत में प्रसारण क्षेत्र के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए हितधारकों से इनपुट इकट्ठा करना है। इस नीति से सामग्री विनियमन, लाइसेंसिंग, टैरिफ संरचनाओं और नयी तकनीकियों और ओटीटी सेवाओं जैसे प्लेटफॉर्मों को शामिल करने सहित विभिन्न मुद्दों को संबोधित किये जाने की उम्मीद है।

ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल के मसौदे की बहुत आलोचना हुई थी, खासकर ओटीटी प्लेटफार्मों को शामिल करने के संबंध में, यह प्रसारण के उभरते परिदृश्य और विभिन्न माध्यमों में सामग्री को विनियमित करने में चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।

ट्राई की भाषा में प्रसारण सेवाओं की परिभाषा में संचार माध्यमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो इलेक्टोमैगनेटिक वेव और केबलों सहित विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक ऑडियो, वीडियो या दोनों के प्रसारण पर जोर देती है। एनबीपी इस तेजी से विकसित हो रहे उद्योग को संचालित करने के लिए व्यापक नीतियों की आवश्यकता पर जोर देता है।

यह अंक सरकार द्वारा जारी नियामक नीतियों का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करता है।

*महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारतीय मीडिया और मनोरंजन (एमएंडई) उद्योग ने **2023** में उल्लेखनीय लचीलापन और विकास का प्रदर्शन किया है। वार्षिक ईवाई रिपोर्ट के अनुसार उद्योग **8%** की वृद्धि के साथ **27.9** बिलियन डॉलर के मूल्य तक पहुंच गया। यह वृद्धि, जो महामारी पूर्व के स्तर से **21%** अधिक है, उद्योग की मजबूती और अनुकूलनशीलता को रेखांकित करती है।*

*रिपोर्ट भारत में स्क्रीन के तेजी से विस्तार पर भी प्रकाश डालती है, **2030** तक लगभग **1** अरब सक्रिय स्क्रीन होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में परंपरा और नवीनता के मिश्रण की विशेषता वाले भारतीय एम एंड ई बाजार की अनूठी विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। यहां, डिजिटल चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म, एआई पावर्ड न्यूजरीडर, पारंपरिक प्रिंट मीडिया, प्रमुख फिल्में और लघु रूप सामग्री एकसाथ मौजूद है और एक साथ पनपती है, जो उद्योग की जीवंत विविधता और गतिशील विकास प्रक्षेवक्र को दर्शाती है। डिजिटल बुनियादी ढ़ांचे को बढ़ाने पर सरकार का ध्यान इस क्षेत्र में परिवर्तन और विस्तार की क्षमताओं को और बढ़ाता है।*

*डिजिटल चैनलों के बढ़ते प्रभुत्व के बावजूद भारत में पारंपरिक मीडिया का विकास जारी है, जिसमें **2023** में कुल विज्ञापन राजस्व का **52%** हिस्सा शामिल है। कुल मिलाकर भारत में एम एंड ई क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जो तकनीकी प्रगति और उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास के लिए तैयार है।*

(Manoj Kumar Madhavan)